

उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार होगी जिला कौशल विकास योजना, युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर

नवबिहार टाइम्स संवाददाता गिरिडीह । समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला कौशल विकास योजना 2026-27 की तैयारियों, स्थानीय उद्योगों की जरूरत, रोजगार की संभावनाओं और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि कौशल विकास का उद्देश्य केवल युवाओं को प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्थायी रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना होना चाहिए। उन्होंने स्थानीय उद्योगों की मानव संसाधन संबंधी जरूरतों का आकलन कर उसी के अनुरूप प्रशिक्षण ट्रेड निर्धारित करने तथा प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिए प्रभावी प्लेसमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।



उन्होंने प्रशिक्षण के बाद युवाओं की रोजगार स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग करने और प्रशिक्षण संस्थानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर

दिया। स्वरोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा बैठक में ऐसे युवाओं की पहचान करने पर जोर दिया गया, जो प्रशिक्षण के बाद अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। उन्हें सरकारी

योजनाओं, बैंक ऋण, वित्तीय सहायता और उद्यमिता संबंधी सुविधाओं से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रशासन ने ह्यप्रशिक्षण से रोजगारहू के साथ ह्यकौशल से

उद्यमिताहू को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ग्रामोध्यम पोर्टल पर 50 उद्यम मॉडल ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नाबाई के सहयोग से विकसित ग्रामोध्यम पोर्टल की जानकारी भी बैठक में साझा की गई। पोर्टल पर बिजनेस आइडिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, बैंक योग्य परियोजना रिपोर्ट, सरकारी योजनाओं, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और बैंक लिंकेज जैसी सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध है।पोर्टल पर ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए 50 एंटरप्रेनेरशिप मॉडल्स उपलब्ध हैं। इनमें खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं डेयरी, अनाज मिलिंग, ग्रीन एनर्जी, थरेल उत्पाद, टेक्स्टाइल, वेल्नेसे, डिजिटल सेवाएं और रिपेरिंग से जुड़े विभिन्न व्यवसाय शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण में स्नैक्स, नुडल्स, नमकीन, बेकरी, जैम-जेली, मसाला, अचार-चटनी आदि, जबकि कृषि एवं डेयरी में मिल्क प्रोसेसिंग, पनीर,

मशरूम प्रोसेसिंग और हाइड्रोपोनिक्स जैसे मॉडल शामिल हैं। वहीं सोलर पैनल असेंबली, बायोमास, वेस्ट रीसाइक्लिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वाहन मरम्मत, कार वॉश और टायर-व्हील सर्विस जैसे क्षेत्रों में भी स्वरोजगार की संभावनाएं बताई गईं। बैठक में जिला प्रशासन ने कौशल प्रशिक्षण रोजगार/प्लेसमेंट तथा कौशल प्रशिक्षण उद्यमिता बैंक ऋण स्वरोजगार की समग्र व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। इससे जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला कौशल विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, कंपनियों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि तथा उनडीपी की टीम के सदस्य मौजूद थे।

खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में भाकपा माले का प्रदर्शन

नवबिहार टाइम्स संवाददाता गिरिडीह। खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में भाकपा माले एवं विभिन्न जनसंगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुफ्सिल थाना क्षेत्र के सदर प्रखंड अंतर्गत महुआटांड स्थित कार्यालय में जुटकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों



के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और विधेयक को वापस लेने की मांग उठाई गई। कार्यक्रम में भाकपा माले जिला कमिटी सदस्य राजेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड की खनिज संपदा और राज्य के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ह्यूझारखंड को केंद्र सरकार बर्बाद करना चाहती है, लेकिन उसकी यह कोशिश सफल नहीं होगी।ह उन्होंने कहा कि खनिज संपदा झारखंड की जनता के अधिकार और विकास का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए किसी भी ऐसी नीति का विरोध किया जाएगा जिससे राज्य के हित प्रभावित हों। वहीं कन्हई पांडेय ने कहा कि झारखंड से भाजपा सरकार को खदेड़े जाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप

भी झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से जुड़े राज्य के हितों को ध्यान में रखने की अपील की। भाकपा माले नेताओं ने कहा कि खनिज संपदा के अलावा राज्य सरकार को मिलने वाले विभिन्न राज्यस्व स्रोतों पर भी केंद्र की नीतियों का असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जर्नहित और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को गांव से लेकर सड़क तक तेज किया जाएगा। इस मौके पर मसूदन कोल, राजेश राय, किशोर राय, भीम कोल, मोहन कोल्ह, प्रदीप कुमार, फेकन राय, गुलाब कोल, रंजीत सिंह, टैटू राय, बुधन राय, नैशद आलम, एकराम अंसारी, मनोज यादव, गांधी और अमन वारसी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।

संक्षिप्त समाचार

आरपीएस महिला कॉलेज में सावन महोत्सव का आयोजन पटना (नवबिहार टाइम्स संवाददाता) । आरपीएस महिला कॉलेज में सावन महोत्सव का आयोजन बड़े उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं तथा सावन मास के महत्व को विद्यार्थियों के बीच प्रोत्साहित करना था। महोत्सव में छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में भाग लिया तथा समूह नृत्य, मेहंदी, राखी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दीं। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. विनीता एवं शिक्षकों ने सावन मास के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला तथा छात्राओं को भारतीय परंपराओं से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

कर्नल कामेश कुमार बने वीवी गिरि विश्वविद्यालय के कुलसचिव सिवान (नवबिहार टाइम्स संवाददाता) । कर्नल कामेश कुमार को वी.बी. गिरि विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किया गया है। वे बिहार के कई प्रमुख राज्य विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय प्रशासन एवं शासन व्यवस्था के क्षेत्र में लगभग आठ वर्षों के समृद्ध और विविध अनुभव के साथ इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालेंगे। कर्नल कामेश कुमार ने थल सेना में कोर ऑफ सिग्नल्स में एक लेफ्टिनेंट के रूप में जून 1987 में योगदान दिया। कर्नल कामेश कुमार का थल सेना में रहते हुए 31 वर्षों का आईटी एवं दूरसंचार क्षेत्र में अनुभव जिसमें मुख्यतः रेडियो संचार नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली, मोबाइल नेटवर्क प्रणाली, आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं संबंधित सुविधाओं, सूचना सुरक्षा नीतियाँ एवं ऑडिट, स्थापना एवं कमीशनिंग, उपकरणों के मूल्यांकन तथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुभव रहा। जिन्होंने दूरसंचार नेटवर्क के के निर्माण, परियोजना के संपूर्ण जीवन-चक्र प्रबंधन, नीतियाँ एवं प्रक्रियाओं के निर्माण, प्रक्रिया सुधार, अनुबंध प्रबंधन, डिलीवरी प्रबंधन, विक्रेता प्रबंधन तथा संबंध एवं प्रदर्शन प्रबंधन में विशेषज्ञता एवं दक्षता दिखायी। इनका साहसिक खेलों का अनुभव भी रहा जिसमें टीम का नेतृत्व करने का अनुभव रहा। यूनिट स्तर पर क्रिकेट एवं वॉलीबॉल में सहभागिता एवं अनुभव भी रहा। एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वविद्यालय के लिए विभिन्न नीतियों एवं प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने का इनका अनुभव भी रहा। कर्नल कामेश कुमार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के संस्थापक कुलसचिव के रूप में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पटना विश्वविद्यालय, मौलाना मजहलुर हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय तथा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कुलसचिव के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

तीन शिक्षण संस्थानों में आयोजित हुआ विद्यार्थी सहयोग शिविर
डंडखोरा/कटिहार (नवबिहार टाइम्स संवाददाता) । सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के आदेश तथा जिला पदाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को प्रखंड क्षेत्र के 03 शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।संस्थान प्रमुख के नेतृत्व में आयोजित इन शिविरों में दंडाधिकारी सहित पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनिगुक्ति की गई थी,तो सभी शिविरों छात्र-छात्राओं उपस्थिति रही।शिविर आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों से उनकी शैक्षणिक, छात्रावास, छात्रवृत्ति, प्रमाण-पत्र, संस्थान की आधारभूत संरचना, पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भोजन, सुरक्षा, परिवहन आदि सुविधाओं की समस्या से संबंधित शिकायतों को प्राप्त कर उनका यथासंभव समाधान सुनिश्चित कराना है। शिविरों में प्राप्त शिकायतों को पंजीकृत कर विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर अपलोड करते हुए समयबद्ध समाधान की कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे स्टेशनों पर पानी की टंकियों और फिल्टरों की होगी विशेष सफाई कटिहार (नवबिहार टाइम्स संवाददाता) । यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर पानी की टंकियों, फिल्टरों और वाटर कूलरों की सफाई व कीटाणुशोधन का विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत क्षेत्रीय रेलवे को पेयजल व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण कर कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर करने का निर्देश दिया गया है। अभियान के दौरान भूमिगत एवं ओवरहेड टैंक, पीवीसी टैंक, जल बूथ, नल, पाइपलाइन, फिल्टर, वाटर कूलर तथा जल वितरण केंद्रों की जांच की जाएगी।

बीएनएसएस पर विशेष व्याख्यान, विधि विद्यार्थियों को नई आपराधिक न्याय व्यवस्था की दी जानकारी

नवबिहार टाइम्स संवाददाता गिरिडीह। कर्माटांड, बेंगाबाद स्थित के. एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के विधि संकाय की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 पर विशेष ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। जूम प्लेटफॉर्म पर आयोजित कार्यक्रम में विधि विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे अर्थार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विधि विशेषज्ञ एवं कानून विषयक पुस्तकों के लेखक मयंक माधव तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज जायसवाल मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। विशेषज्ञों ने बीएनएसएस के प्रमुख प्रावधानों, उसके व्यावहारिक उपयोग, न्यायिक प्रक्रिया में हुए बदलाव तथा पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) से इसके महत्वपूर्ण अंतरों पर

विस्तार से प्रकाश डाला।मयंक माधव ने विद्यार्थियों को बताया कि नए आपराधिक कानूनों को केवल धाराओं के रूप में याद करने के बजाय उनके उद्देश्य, प्रक्रिया और व्यावहारिक प्रभाव को समझना जरूरी है। उन्होंने न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बीएनएसएस के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी।वहीं, पंकज जायसवाल ने न्यायालयीन अनुभव साझा करते हुए आपराधिक न्याय प्रक्रिया में तकनीक और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक समयबद्ध बनाने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को नवीनतम कानूनी बदलावों और न्यायालयों के महत्वपूर्ण नियमों का नियमित अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज के विधि संकाय के प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार ने कहा कि विधि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम

तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। नए कानूनों और न्यायिक बदलावों से विद्यार्थियों को लगातार अवगत कराना शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के बाद आपराधिक न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। कार्यक्रम के बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं, न्यायिक प्रक्रिया तथा पुराने और कानूनों के बीच अंतर से जुड़े सवाल पूछे। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। संविधान पर हुई प्रश्नोत्तरी विशेष व्याख्यान के बाद विद्यार्थियों के संवैधानिक एवं विधिक ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से ह्यसंविधानहू विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई।

नवबिहार टाइम्स संवाददाता गिरिडीह। रक्षाबंधन के अवसर पर बीएनएस डीएवी विद्यालय की नन्हें छात्राएं मंगलवार को गिरिडीह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचीं। छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार, भा.पु.से. को राखी बांधकर भाई-बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का संदेश दिया। छात्राओं के हाथों राखी बंधवाने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार ने सभी बच्चियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि



रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का पर्व नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है। एसपी ने छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने और अपने सपनेओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। छात्राओं की इस आत्मीय पहल से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खुशी और उत्साह का माहौल रहा। इस मौके ने पुलिस और आमजन के बीच विश्वास, अपनापन और आत्मीय संबंधों को और मजबूत करने का संदेश दिया।

मंटू मुर्मू पर भीड़ द्वारा हमला करने का आरोप, एससी-एसटी थाना में आवेदन

नवबिहार टाइम्स संवाददाता गिरिडीह। 21 अगस्त को झंडा मैदान में हुई घटना को लेकर मंगलवार को होटल गैली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जयएससी-जेपीएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े मंटू मुर्मू ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने उनके साथ मारपीट की और मौब लिचिंग का प्रयास किया। मंटू मुर्मू ने बताया कि जयएसएससी- जेपीएससी रिफॉर्म मंच की ओर से झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में गिरिडीह में भी युवाओं ने 21 अगस्त की शाम छह बजे पुतला दहन करने का निर्णय लिया था। इसी दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से टावर चौक पर केंद्र सरकार के खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। आरोप है कि इसी बीच करीब 200 से 250 की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता झंडा मैदान पहुंच गए। मंटू मुर्मू ने आरोप लगाया कि लखन राम, मोहम्मद असलम, सनी राईन, संजय सिंह, अजीत पप्पू, सुमित कुमार, मोहम्मद राय समेत अन्य लोगों ने उन्हें भीड़ के बीच खींच लिया।

सीसीएल का लंकास्टर अस्पताल धंसा, जमीन में पड़ीं दरां
नवबिहार टाइम्स संवाददाता गिरिडीह। सीसीएल गिरिडीह एरिया में मंगलवार की अहले सुबह अचानक हुए भू-धंसान से हड़कंप मच गया। भू-धंसान की चपेट में सीसीएल का लंकास्टर अस्पताल भी आ गया। अस्पताल की दो इमारतें चुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि भवन का एक हिस्सा जमीन में धंस गया। अस्पताल परिसर से लगी सड़क और आसपास के बड़े भू-भाग में भी चौड़ी-चौड़ी दरारें पड़ गईं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही सीसीएल गिरिडीह एरिया के जीएम कन्हैया शंकर गैवाल, परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीणा, चिकित्सा पदाधिकारी परियल सिन्हा, सिविल विभाग के रामाकांत समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और



स्थिति का जायजा लिया। अस्पताल कमीं दिलीप कुमार के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब चार बजे जमीन और भवन में धंसान दिखाई दिया। स्थिति को देखते हुए अस्पताल में मौजूद सभी कर्मियों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया क भू-धंसान के बाद सीसीएल अधिकारियों ने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। एहतियात के तौर पर अस्पताल क्षेत्र में लोगों की आवाजाही रोकने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया गया।

फर्जी सरकारी नोटिस भेजकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

नवबिहार टाइम्स संवाददाता गिरिडीह। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुफर्रिसल थाना क्षेत्र के सिहोडीह स्थित बिंदू पांडेय के मकान में छापेमारी कर साइबर ठगी के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन साइबर आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछाछाड़ में पुलिस को बताया कि वे आंगनबाड़ी का फर्जी



नोटिस, गैस बिल अपडेट, गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं को एकाउंट फुल करवाने से संबंधित फर्जी नोटिस, महानगर गैस लिमिटेड तथा एलपीजी गैस कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने से संबंधित फर्जी नोटिस भेजकर

लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ताराटांड थाना एलपीजी गैस कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने से संबंधित फर्जी नोटिस भेजकर

मिलाद-उन-नबी को लेकर पुलिस लाइन में माँक ड्रिल

नवबिहार टाइम्स संवाददाता गिरिडीह। आगामी मिलाद-उन-नबी पर्व को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को पुलिस लाइन परिसर में माँक ड्रिल आयोजित कर आपात स्थिति से निपटने, भीड़ नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई का अभ्यास कराया गया। माँक ड्रिल का निरीक्षण उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार एवं उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने किया। इस दौरान सुरक्षा बलों की तत्परता, आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, संवेदनशील परिस्थितियों में संयमित कार्रवाई और प्रशासन-पुलिस के बीच बेहतर समन्वय का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि



मिलाद-उन-नबी पर्व के दौरान जिले में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को पूरी गंभीरता और सजगता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने तथा किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एसपी डॉ. बिमल कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी

रखने तथा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया। माँक ड्रिल के माध्यम से संभावित चुनौतियों से निपटने और उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल का अभ्यास कराया गया। जिला प्रशासन ने पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के साथ आमजनों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की है।

विधायकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा और लंबित मामलों के निपटारे पर विधानसभा अध्यक्ष सख्त

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ बैठक में डॉ. प्रेम कुमार ने दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में मुख्य सचिव बिहार प्रत्यय अमृत के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में विधानसभा के सदस्यों, सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को शीघ्र कैशलेस करने, विधायकों के बैठने की व्यवस्था तथा वर्षों से लंबित संसदीय समिति के मामलों और विभागीय आश्वासनों के निष्पादन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों एवं सभा सचिवालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति में आ रही कठिनाइयों पर चिंता जताई। उन्होंने संबंधित प्रक्रिया को यथाशीघ्र कैशलेस व्यवस्था में बदलने का निर्देश दिया, ताकि चिकित्सा सुविधाओं के लाभ



में किसी प्रकार की परेशानी न हो। डॉ. प्रेम कुमार ने सदस्यों के बैठने और आम लोगों से मिलने की सुविधा को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में इसके लिए उपयुक्त स्थान अथवा भूखंड चिह्नित कर भवन का निर्माण कराया जाए। जहां नई व्यवस्था संभव नहीं हो, वहां पंचायत भवन में ही आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार किया

जा सकता है। बैठक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों से जुड़े लंबित मामलों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2008-09 से अब तक लोक लेखा समिति एवं लोक उपक्रम समिति की लगभग 2499 कंडिकाएं, उप-कंडिकाओं सहित लंबित हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित वर्ष 1995 से 2025 तक लगभग 23,517

आश्वासन भी वर्तमान में लंबित बताए गए हैं। इन मामलों की बड़ी संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. प्रेम कुमार ने मुख्य सचिव को समिति और संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर चालू वित्तीय वर्ष में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने बिहार विधानसभा की संसदीय समितियों की विभागीय

बैठकों में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अथवा सचिव की अनुपस्थिति पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति में कम से कम विशेष सचिव स्तर अथवा उससे ऊपर के अधिकारी को विधिवत प्राधिकार पत्र के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए अधिकृत किया जाए। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने विधानसभा अध्यक्ष को आश्चस्त किया कि वे सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के साथ बैठक कर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बैठक में बिहार विधानसभा की प्रभारी सचिव सहित सभा सचिवालय के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

‘विद्यार्थी सहयोग पोर्टल’ से छात्रों की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचेगी : संजय सरावगी

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने छात्रों के प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर कहा कि बिहार सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार छात्रों एवं नौजवानों के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। विद्यार्थियों की समस्याओं और सुझावों को सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए आज ही ‘विद्यार्थी सहयोग पोर्टल’ का

शुभारंभ किया गया है। इससे छात्रों की आवाज संस्थागत तरीके से सरकार तक पहुंचेगी और उनकी समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया और प्रभावी होगी। संजय सरावगी ने कहा कि बिहार सरकार ने छात्रों की प्रमुख मांगों में शामिल शिक्षक भर्ती के लिए टीआरड-4 के तहत 32,388 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब लगभग 20 हजार पदों की मांग की जा रही थी, तब सरकार ने उससे कहीं अधिक 32,388 पदों पर भर्ती का रास्ता खोल दिया।

लोक संस्कृति और विविधता में एकता का प्रतीक लोकोत्सव : विजय प्रकाश

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना/दानापुर। दानापुर स्थित ‘स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग’ में पारंपरिक लोक संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित ‘लोकोत्सव’ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वागत आरती के साथ हुई। इसके उत्स्रांत एक अनूठे और प्रतीकात्मक अंदाज में दीप प्रज्वलन संपन्न हुआ जिसमें देश की चार अलग-अलग दिशाओं से चार राज्यों के प्रतिनिधि और केंद्र में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए



कुल पांच स्वरूपों ने एक साथ मिलकर दीप प्रज्ज्वलित किया। इस प्रस्तुति ने विविधता में एकता के भारतीय दर्शन को जीवंत कर दिया। दीप प्रज्वलन के बाद लोकोत्सव और भारतीय परंपराओं के महत्व पर विशेष वक्तव्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद आयोजित

केवाड़पी केंद्रों की मांगों को लेकर पटना में धरना-प्रदर्शन, संचालकों ने उठाई आवाज



नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। बिहार में संचालित कुशल युवा कार्यक्रम केंद्रों के नवीनीकरण, लॉबित भुगतान और प्रशिक्षण कार्य तत्काल शुरू कराने की मांग को लेकर मंगलवार को पटना के गर्दनीबाग में केंद्र संचालकों एवं संबंधित लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में विभिन्न मांगों से संबंधित तख्तायें लेकर सरकार और विभाग से केवाड़पी केंद्रों के भविष्य को लेकर तत्काल निर्णय लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान ‘कौशल विकास हमारा अधिकार’, ‘रोजगार और सम्मान-कौशल

विकास हमारी पहचान’ जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से संपूर्ण बिहार में केवाड़पी केंद्रों में प्रशिक्षण कार्य प्रभावित है तथा केंद्र संचालकों का भुगतान भी आठ माह से लंबित है। उन्होंने पुराने संचालित केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर नवीनीकरण देने और केवाड़पी प्रशिक्षण तत्काल प्रारंभ करने की मांग की। केंद्र संचालकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को लेकर तत्काल निर्णय लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान ‘कौशल विकास हमारा अधिकार’, ‘रोजगार और सम्मान-कौशल

सावन की मस्ती के साथ दिखी शिक्षिकाओं और माताओं की प्रतिभा

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। रकनपुरा स्थित किड्सजोन - एन एलीमेंट्री स्कूल द्वारा द रेड गार्डन हॉल में सावन के अवसर पर सावन संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों, शिक्षिकाओं और माताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। नृत्य, किंगज, रैप वॉक, मनोरंजक खेल और टैलेन्ट शो जैसी गतिविधियों ने पूरे आयोजन को खास बना दिया। सावन क्वीन प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया जिसमें सोनाली राज ने सावन क्वीन का खिताब जीता। सावन क्वीन प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में स्कूल की प्राचार्या प्रितीमा सिंह, सिमा प्रभात, मनोज एवं



सुजाता मौजूद रहे। स्कूल की प्राचार्या प्रितीमा सिंह ने कहा कि सावन संगम के आयोजन का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ कला, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। इस तरह भाग लिया जिसमें सोनाली राज ने सावन क्वीन का खिताब जीता। सावन क्वीन प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में स्कूल की प्राचार्या प्रितीमा सिंह, सिमा प्रभात, मनोज एवं

सुजाता मौजूद रहे। स्कूल की प्राचार्या प्रितीमा सिंह ने कहा कि सावन संगम के आयोजन का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ कला, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। इस तरह भाग लिया जिसमें सोनाली राज ने सावन क्वीन का खिताब जीता। सावन क्वीन प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में स्कूल की प्राचार्या प्रितीमा सिंह, सिमा प्रभात, मनोज एवं

अतिथि शिक्षकों के सेवा समायोजन की दिशा में बड़ी पहल, मुख्यमंत्री के आश्वासन से खुशी की लहर

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। राज्य के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों (सहायक प्राध्यापकों) के सेवा समायोजन को लेकर बड़ी पहल सामने आई है। 22 दिनों से धरना स्थल पर आमरण अनशन कर रहे अतिथि शिक्षकों के मामले में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के स्तर पर सकारात्मक पहल के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के विधायक एवं जदयू जिलाध्यक्ष राजेश मंडल उर्फ ईश्वर मंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अतिथि शिक्षकों को



65 वर्ष तक सेवा सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक आश्वासन दिया है। विधायक ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लगातार मुलाकात कर अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग रखी थी। विधायक ईश्वर मंडल ने कहा कि

वर्ष 2019 में नियुक्त अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापन कार्य के अतिरिक्त अन्य रोजगार नहीं करने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश का पालन करते हुए शिक्षक वर्षों से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सहायक

प्राध्यापकों की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ऐसे में यदि उससे पहले अतिथि शिक्षकों के सेवा समायोजन पर निर्णय नहीं लिया गया तो हजारों शिक्षकों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है, जो वर्तमान में निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं और नई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह सकते हैं। श्री मंडल ने बताया कि बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति की ओर से भी अतिथि शिक्षकों के सेवा समायोजन की अनुशंसा की जा चुकी है।

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वर्तमान मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद द्वारा मंगलवार को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर मौजूद थे। समीक्षा बैठक में पर्षद के सदस्य-सचिव नीरज नारायण, पर्षद के वैज्ञानिक सलाहकार एसएम जायसवाल, वैज्ञानिक, डॉ. नवीन कुमार एवं वैज्ञानिक अरूण कुमार, पर्यावरण अभियंता एके गुप्ता तथा पप्पू कुमार, तकनीकी सलाहकार, एक्ज्युएम सेल भी उपस्थित थे। बैठक में मंत्री का पर्षद



मुख्यालय में स्वागत करते हुए सदस्य-सचिव नीरज नारायण द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर मौजूद थे। समीक्षा बैठक में पर्षद के सदस्य-सचिव नीरज नारायण, पर्षद के वैज्ञानिक सलाहकार एसएम जायसवाल, वैज्ञानिक, डॉ. नवीन कुमार एवं वैज्ञानिक अरूण कुमार, पर्यावरण अभियंता एके गुप्ता तथा पप्पू कुमार, तकनीकी सलाहकार, एक्ज्युएम सेल भी उपस्थित थे। बैठक में मंत्री का पर्षद

सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में लाएं तेजी : श्रवण कुमार

नवबिहार टाइम्स संवाददाता



जाए। उन्होंने नकारात्मक खबरों के त्वरित आधिकारिक खंडन पर भी जोर दिया, ताकि गलत जानकारी या अफवाहें न फैले। **सोशल मीडिया पर योजनाओं के प्रचार की नियमित समीक्षा** श्री कुमार ने विभाग को मीडिया संबंधी कार्यों को और सुचारू व मजबूत बनाने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया में बढ़ती रुचि को देखते हुए उन्होंने सरकार और आमजन के बीच विश्वास व सकारात्मक रवैया अपनाने पर बल

दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यों का फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म पर उत्तम गुणवत्ता के साथ नियमित प्रचार हो और इसकी नियमित समीक्षा भी की जाए। कार्यालय में कार्य समन्वय और पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने विभाग के सचिव नवीन कुमार, निदेशक अनिल कुमार, संयुक्त सचिव राजीव कुमार सिंह सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बी. डी. कॉलेज में विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। बिहार सरकार की योजना ‘सखम सम्मान, जीवन आसान’ के अंतर्गत विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से बी. डी. कॉलेज, पटना में मंगलवार को ‘विद्यार्थी सहयोग शिविर’ का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. दिवाकर प्रसाद के संरक्षण एवं नोडल पदाधिकारी के निदेशन में किया गया। शिविर में विद्यार्थियों से प्राप्त विभिन्न शैक्षणिक एवं अन्य समस्याओं पर आवश्यक विचार-विमर्श करते हुए नियमानुसार कार्रवाई एवं समाधान किया गया। शिविर में प्रो. शत्रुघ्न शरण सिंह, डॉ. बिनोद कुमार, डॉ. निखिलानंद ठाकुर, डॉ. राजीव कुमार (राजनीतिक विज्ञान), डॉ.



राजीव कुमार, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. स्वर्णा कुमार, डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. कुमारी मोनिका, डॉ. सुजान दत्ता, डॉ. रवि रंजन, डॉ. विनीता तिवारी एवं डॉ. नंदिनी नारायण सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। शिविर में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं एवं आवेदनों पर आवश्यक विभागीय विमर्श करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई। आज की रिपोर्ट के अनुसार कुल 08 मौखिक

समस्याएं प्राप्त हुईं जिनका आवश्यक समाधान किया गया। लिखित रूप में प्राप्त आवेदन एवं लंबित आवेदन की संख्या शून्य रही। महाविद्यालय प्रशासन ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान, उनके हितों की रक्षा तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के विद्यार्थी सहयोग शिविर आगे भी प्रभावी रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे।

रेलकर्मियों ने महाप्रबंधक से मुलाकात कर समस्याओं से कराया अवगत



नवबिहार टाइम्स संवाददाता

हाजीपुर। मुख्यालय, हाजीपुर में 7 रेलकर्मों/उनके आश्रितों ने पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह से मुलाकात की तथा अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। महाप्रबंधक ने संबंधित विभागों को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में केस निष्पादन के निर्देश दिए।

रेलकर्मियों एवं उनके आश्रितों की विभागीय समस्याओं के निष्पादन के उद्देश्य से महाप्रबंधक से मुलाकात हेतु प्रत्येक मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया है। इसके लिए रेलकर्मों अपना नाम पूर्व में कार्मिक विभाग में पंजीकृत करवाकर मंगलवार को महाप्रबंधक से मुलाकात कर अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकते हैं।

सावन की सांस्कृतिक छटा से सराबोर हुआ देशरत्न राजेंद्र प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

गीत, नृत्य, भजन और लोक प्रस्तुतियों से प्रशिक्षुओं ने बांधा समा

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। सावन की हरितिमा, भक्ति, लोकजीवन की उमंग और भारतीय संस्कृति की विविध छवियां आज देशरत्न राजेंद्र प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सदाकत आश्रम, पटना के परिसर में जीवंत हो उठीं। सावन महोत्सव के अवसर पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रशिक्षुओं ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए वातावरण को उत्सवमय बना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बिहार विद्यापीठ के अध्यक्ष एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पदाधिकारी विजय



प्राकाश ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा में ऋतुओं और पर्वों का विशेष महत्व रहा है। यहां उत्सव केवल आनंद का अवसर नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, समाज में सहयोग और सीमित नहीं है। भावी शिक्षक आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शक होने के साथ-साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संवाहक भी हैं।

को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और लोक परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों का दायित्व केवल विषयगत ज्ञान तथा सीमित नहीं है। भावी शिक्षक आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शक होने के साथ-साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संवाहक भी हैं।

प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में राज्य पर्षद द्वारा किये जा रहे कार्यों की मंत्री ने की सराहना

मानकों को दृढ़तापूर्वक लागू करने का दिया निर्देश

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वर्तमान मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद द्वारा मंगलवार को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर मौजूद थे। समीक्षा बैठक में पर्षद के सदस्य-सचिव नीरज नारायण, पर्षद के वैज्ञानिक सलाहकार एसएम जायसवाल, वैज्ञानिक, डॉ. नवीन कुमार एवं वैज्ञानिक अरूण कुमार, पर्यावरण अभियंता एके गुप्ता तथा पप्पू कुमार, तकनीकी सलाहकार, एक्ज्युएम सेल भी उपस्थित थे। बैठक में मंत्री का पर्षद



मुख्यालय में स्वागत करते हुए सदस्य-सचिव नीरज नारायण द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर मौजूद थे। समीक्षा बैठक में पर्षद के सदस्य-सचिव नीरज नारायण, पर्षद के वैज्ञानिक सलाहकार एसएम जायसवाल, वैज्ञानिक, डॉ. नवीन कुमार एवं वैज्ञानिक अरूण कुमार, पर्यावरण अभियंता एके गुप्ता तथा पप्पू कुमार, तकनीकी सलाहकार, एक्ज्युएम सेल भी उपस्थित थे। बैठक में मंत्री का पर्षद

सहायक नदियों के जल का नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण कर उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहरों में एसटीपी की स्थापना से मल-संबंधी कोलीफॉर्म की औसत मात्रा 2199 एम्पीएन /100 एमएल दर्ज की गयी है, जो निर्धारित मानक (2500 एम्पीएन/100 एमएल) से कम है। पर्षद द्वारा राज्य के 23 जिलों में कुल 35

अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र संचालित हैं, जिनके माध्यम से परिवेशीय वायु गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। पर्वर राज्य के बेहतर पर्यावरण के लिए सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2025-26 में पीएम 10 की सांद्रता में 55.15 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। इसी प्रकार पीएम 2.5 की सांद्रता में 2022-23 की तुलना में वर्ष 2025-26 में 52.54 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। राज्य में कुल 58 औद्योगिक इकाइयों जहां पर तेल कम्पनियों द्वारा स्वच्छ ईंधन के रूप में पीएनजी की आपूर्ति नेटवर्क विकसित है।



संपादकीय

कागजों पर ‘असुरक्षित’ जमीन पर बेपरवाही, करोल बाग हादसे ने खोली व्यवस्था की पोल

जर्जर इमारतें सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण हादसों का सबब बन रही हैं। करोल बाग हादसा प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। असुरक्षित मकानों को तुरंत खाली कराकर सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी है। देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी एवं जर्जर इमारतें आम लोगों के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। कई बार स्थानीय

प्रशासन की ओर से ऐसी इमारतों को ‘असुरक्षित’ तो घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें खाली कराने में कोई तत्परता या गंभीरता नजर नहीं आती है।यही नहीं, कई दफा जर्जर भवन को मालिक खुद ही गिरा देते हैं, लेकिन इस कार्य में सुरक्षा के माकूल प्रबंधों का अभाव भी हादसे का कारण बन जाता है। ऐसी ही एक घटना बीते शुक्रवार को दिल्ली के करोल बाग

इलाके में हुई, जब पुरानी दो मंजिला इमारत के ध्वंसीकरण के दौरान एक श्रमिक की जान चली गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।पुलिस के मुताबिक, इस इमारत को गिराने के लिए सरकार के संबंधित महकमे से अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में सवाल है कि अगर नियमों और सुरक्षा उपायों की अनदेखी की जाती है, तो क्या इसके लिए विभागीय अधिकारियों की

भी जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए?गौरतलब है कि पुराने खस्ताहाल मकान हर साल खासकर बरसात के मौसम में लोगों की जान के लिए खतरा बन जाते हैं। यह समस्या खास तौर पर उन शहरों में ज्यादा गंभीर है, जहां घनी आबादी और पुरानी बस्तियां हैं। देश भर में जर्जर इमारतों को चिह्नित कर उन्हें सरकारी दस्तावेज में असुरक्षित घोषित करने की व्यवस्था पहले

से मौजूद है।मगर स्थानीय प्रशासन का इस ओर ध्यान कम ही जाता है। जिन पुराने भवनों को असुरक्षित घोषित किया जाता है, उन्हें खाली कराने, गिराने या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी वर्षों तक अटकी रहती है। यह विभागीय लापरवाही का ही नतीजा होता है कि ऐसी इमारतें कई बार हादसों का कारण बन जाती हैं।सवाल यह भी है कि करोल बाग इलाके में इमारत का ध्वंसीकरण

विभागीय अनुमति के बिना कैसे हो रहा था? जर्जर भवनों की पहचान करना और उन्हें गिराने के कार्य की निगरानी करना किसकी जिम्मेदारी है?कायदे से असुरक्षित इमारतों का नियमित वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना चाहिए और उनकी श्रेणीबद्ध सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए। साथ ही उन्हें खाली कराने और गिराने के लिए स्पष्ट नीति एवं योजना का होना भी जरूरी है।

अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। ‘डीपफेक’ ने वास्तविक और कृत्रिम के बीच की रेखा धुंधली कर दी है। किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरा और हाव-भाव को इतनी सहजता से बदला जा सकता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए सत्य और असत्य में अंतर करना कठिन हो जाता है। इससे गलत सूचना का खतरा ही नहीं बढ़ता, बल्कि सामाजिक विश्वास की नींव भी कमजोर होती है। ऐसी स्थिति में समाधान संतुलित होना चाहिए, कठोर सेंसरशिप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। डिजिटल मंचों को पूरी तरह अनियंत्रित छोड़ना भी उचित नहीं है, क्योंकि वे जनमत निर्माण की अत्यंत प्रभावशाली शक्ति बन चुके हैं।

डिजिटल युग में ‘सत्य’ की परीक्षा- सूचना की बाढ़ में खोता सामाजिक भरोसा

(अतुल अग्रवाल)

डिजिटल क्रांति ने सूचना प्रवाह को तेज किया है, पर एआई डीपफेक और फेक न्यूज से सामाजिक भरोसा कम हुआ है। सत्य की रक्षा के लिए पारदर्शी नियमन, डिजिटल साक्षरता और जागरूक नागरिक की साझा जिम्मेदारी जरूरी है। एक समय था जब सूचनाएं समाज तक पहुंचने से पहले सत्यापन, संपादन और विवेक की अनेक कसौटियों से गुजरती थीं। अखबारों, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित समाचारों के पीछे पत्रकारिता की नैतिकता और संपादकीय उत्तरदायित्व होता था। सूचना का प्रवाह भले ही आज की तुलना में धीमा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका भरोसा था।मगर डिजिटल क्रांति ने संचार की इस पूरी संस्कृति को बदल दिया है। आज कोई अफवाह, अधूरा वीडियो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार तस्वीर, किसी भाषण का काट-छाट किया गया अंश या किसी गुप्तनाम व्यक्ति की पोस्ट कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसी सामग्री के सही या गलत होने पर बहस बाद में होती है, लेकिन तब तक वह लोगों की सोच और सामाजिक धारणाओं को प्रभावित कर चुकी होती है।

इसलिए आज की सबसे बड़ी चुनौती केवल झूठी सूचनाओं का प्रसार ही नहीं, बल्कि सत्य के प्रति समाज के भरोसे का कमजोर पड़ना भी है। निस्संदेह, डिजिटल माध्यमों ने संवाद को अधिक लोकतांत्रिक बनाया है। साधारण नागरिक भी घटनास्थल से तत्काल तस्वीरें और वीडियो साझा कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों का समन्वय तेज हुआ है। छोटे उद्यमियों को नए अवसर मिले हैं, कलाकारों और लेखकों को वैश्विक मंच मिला है तथा शिक्षा एवं शोध भौगोलिक सीमाओं से काफी हद तक मुक्त हुए हैं। जिन समुदायों की आवाज कभी मुख्यधारा तक नहीं पहुंचती थी, उन्हें भी अपने विचार रखने का अवसर मिला है। मगर तकनीक की यही शक्ति उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई है। डिजिटल मंचों की कार्यप्रणाली का उद्देश्य अक्सर सत्य की खोज से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है।

इसलिए संतुलित विश्लेषण की तुलना में सनसनी, तर्क की अपेक्षा भावनाएं और तथ्यों की तुलना में उत्तेजक सामग्री अधिक प्रभावशाली हो जाती है। क्रोध, भय और पूर्वाग्रह जैसी भावनाएं तेजी से फैलती हैं, जबकि संयमित और तथ्य आधारित व्याख्या पीछे छूट जाती है। लोग सोचने से पहले प्रतिक्रिया देने लगते हैं। भ्रामक सूचना कोई नई सामाजिक समस्या नहीं है। इतिहास अफवाहों, दुष्प्रचार और अतिशयोक्ति का साक्षी रहा है। अंतर केवल इतना है कि पहले झूठ को फैलाने में समय लगता था, जबकि आज तकनीक ने उसे अभूतपूर्व गति और व्यापक पहुंच दे दी है।

जब कोई असत्य बार-बार दोहराया जाता है, तो वह सच जैसा प्रतीत होने लगता है। अधिकांश लोग किसी संदेश को साझा करने से पहले उसके स्रोत की पड़ताल नहीं करते। झूठ सिर्फ इसलिए सफल नहीं होता कि उसके पीछे मिथ्या तर्कों का जाल बुना होता है, बल्कि इसलिए सफल होता है कि वह सत्य से पहले लोगों तक पहुंच जाता है और उनकी भावनाओं को प्रभावित करता है। इसके दुष्परिणाम सार्वजनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं।

चुनावों के दौरान भ्रामक आंकड़े, संदर्भ से काटे गए वीडियो और दुष्प्रचार के अभियान मतदाताओं को भ्रमित करते हैं। भारत जैसे बहुलतावादी समाज में सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने कई बार सांप्रदायिक तनाव को भी जन्म दिया। इससे स्पष्ट है कि आभासी दुनिया में फैलाया गया झूठ वास्तविक दुनिया में गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है।

अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। ‘डीपफेक’ ने वास्तविक और कृत्रिम के बीच की रेखा धुंधली कर दी है। किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरा और हाव-भाव को इतनी सहजता से बदला जा सकता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए



सत्य और असत्य में अंतर करना कठिन हो जाता है। इससे गलत सूचना का खतरा ही नहीं बढ़ता, बल्कि सामाजिक विश्वास की नींव भी कमजोर होती है। ऐसी स्थिति में समाधान संतुलित होना चाहिए, कठोर सेंसरशिप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है।

डिजिटल मंचों को पूरी तरह अनियंत्रित छोड़ना भी उचित नहीं है, क्योंकि वे जनमत निर्माण की अत्यंत प्रभावशाली शक्ति बन चुके हैं। जरूरत ऐसी व्यवस्था की है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच स्वस्थ संतुलन स्थापित करे। यदि सोशल मीडिया मंच पर किसी सामग्री को हटाय़ा या सीमित किया जाता है, तो प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष होनी चाहिए। इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि तकनीकी कंपनियां अब केवल संचार का माध्यम नहीं हैं, वे समाज के वैचारिक परिवेश को आकार देने वाली संस्थाएं बन गई हैं।

उनके डिजिटल ढांचे इस बात को प्रभावित करते हैं कि लोग क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे और किन विषयों पर चर्चा करेंगे। इसलिए उन्हें अपनी कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी बनानी होगी, भारतीय भाषाओं में तथ्य-जांच की सशक्त व्यवस्था विकसित करनी होगी, भ्रामक सामग्री पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित सामग्री को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना होगा।

साथ ही सामग्री नियमन से जुड़े निर्णय स्वतंत्र निगरानी और सार्वजनिक समीक्षा के दायरे में होने चाहिए।

इस परिदृश्य में पारंपरिक पत्रकारिता की भूमिका भी पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सूचना की बाढ़ के दौर में केवल तथ्य प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है, उनके संदर्भ, पृष्ठभूमि और प्रभाव को समझना भी आवश्यक है। इसमें डिजिटल साक्षरता की भी अहम भूमिका है। नागरिकों को यह समझना जरूरी है कि कौन-सी सूचना विश्वसनीय है, कौन-सा वीडियो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, कौन-सी भाषा केवल भावनाएं भड़काने के लिए प्रयुक्त हुई है और किन तथ्यों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जानी चाहिए।



दरअसल, आज आवश्यकता तत्काल प्रतिक्रिया देने के बजाय विचारपूर्वक निर्णय लेने की संस्कृति विकसित करने की है। हर सूचना पर तुरंत विश्वास करना जितना खतरनाक है, उतना ही जोखिमपूर्ण उसे बिना कारण अनदेखा करना भी है। परिपक्व लोकतांत्रिक समाज वही है जहां नागरिक प्रश्न पूछते हैं, प्रमाण तलाशते हैं और पर्याप्त तथ्य उपलब्ध होने तक निर्णय सुरक्षित रखने का धैर्य रखते हैं। यह बौद्धिक धैर्य लोकतंत्र की बड़ी शक्ति है।

आभासी दुनिया में भ्रामक सूचनाओं की चुनौती का समाधान सरकार, तकनीकी कंपनियों, मीडिया, शिक्षा जगत और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। सरकार को स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलित कानून बनाने होंगे। तकनीकी कंपनियों को सार्वजनिक विमर्श पर अपने प्रभाव को स्वीकार करते हुए अधिक जवाबदेह बनना होगा। शिक्षा जगत को आलोचनात्मक चिंतन और डिजिटल साक्षरता को आवश्यक कौशल बनाना होगा।

प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि वह केवल सूचना का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसके प्रसार की शृंखला का उत्तरदायी हिस्सा भी है। डिजिटल क्रांति ने मानवता को संवाद, सहयोग और नवाचार की असीम संभावनाएं दी हैं। इन उपलब्धियों को सुरक्षित रखने के लिए सत्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के प्रति समान प्रतिबद्धता आवश्यक है।

वंदे मातरम् पर विवाद क्यों? असहमति से पंथनिरपेक्षता तक छिड़ी नई बहस

(राकेश सिन्हा)

‘वंदे मातरम्’ के उन चार अंतर्गों में क्या है, जिसे पंथनिरपेक्षता के प्रतिकूल कहा जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर भारत की मौलिकता की खोज है। उन्हें सबसे आपत्तिजनक ‘दुर्गा’ (विद्या और ज्ञान वाहिनी या रिपुदलवारिणी, जिसका तात्पर्य है शत्रुओं का विनाश करने वाली) का उल्लेख लगता है। असहमति और आक्रोश या नापसंदगी और नफरत के बीच अंतर होता है। असहमति और नापसंदगी वैचारिक एवं तर्क पर आधारित होती है, जबकि आक्रोश और नफरत की बुनियाद प्रतियोगी एवं ताकत होती है। उदाहरण के लिए ‘वंदे मातरम्’ को संपूर्णता में गाने पर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की असहमति एवं इसके प्रति नापसंदगी थी। मगर स्वतंत्र भारत में कोई इस तरह का विरोध करता है, तो यह अनपेक्षित है। ‘वंदे मातरम्’ ने स्वदेशी, राष्ट्रीयता और उपनिवेशवाद-विरोध को ताकत दी थी और लोगों ने इसे गाते-गाते बलिदान दिया था। इनमें दो नाम उल्लेखनीय हैं। ओडिशा के बाजी राउत और असम की तिलेश्वरी बरुआ। दोनों की उम्र मात्र बारह वर्ष थी। औपनिवेशिक सरकार की ओर से इस गीत को गाने पर प्रतिबंध का लोगों ने विरोध किया और जेल गए। आज कांग्रेस की आक्रामकता इतनी अधिक है कि इसे संपूर्णता में गाने की जगह वे जेल जाना पसंद कर रहे हैं। ‘वंदे मातरम्’ के उन चार अंतर्गों में क्या है, जिसे पंथनिरपेक्षता के प्रतिकूल कहा जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर भारत की मौलिकता की खोज है। उन्हें सबसे आपत्तिजनक ‘दुर्गा’ (विद्या और ज्ञान वाहिनी या रिपुदलवारिणी, जिसका तात्पर्य है शत्रुओं का विनाश करने वाली) का उल्लेख लगता है। इनमें न किसी धर्म पर प्रहार है और न ही ये कर्मकांड के वे अंश हैं, जो सभी रूपक के रूप में उपयोग किए गए हैं। तभी भारत के मुसलमानों को 1937 से पहले इस पर कोई आपत्ति नहीं थी।

‘वंदे मातरम्’ और ऐतिहासिक विवाद –वर्ष

1937 में प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दो साल के बाद लीग ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसे ‘पीरपुर रिपोर्ट’ कहते हैं। इसमें कांग्रेस शासन को ‘अल्पसंख्यक विरोधी’ कहा गया। आपत्ति के विषय को इसी से जाना जा सकता है कि महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने, तिरंगा फहराने, वंदे मातरम् गाने जैसी

दर्शन और अध्यात्म के बीच विभाजन रेखा ढूंढना कठिन है। यही नेहरूवाद का नजरिया रहा था, जिसके कारण दर्शन के क्षेत्र में समृद्ध भारत के विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन में गिरावट आई है। ऐसे में तो वेद, महाभारत, पुराण, उपनिषद- सब में अध्यात्म का अंश है, तो क्या वे पंथनिरपेक्ष साहित्य नहीं माने जाएंगे? वे



बातों को हिंदू फासीवादी होने का आधार बनाया गया। जिस लीग की तर्ज पर कांग्रेस चल रही है, वह भारत की मौलिकता को समाप्त करने का उपक्रम है। वर्ष 1920 में नागपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने मंच पर गांधी को ‘महात्मा’ की जगह ‘मिस्टर’ कहकर संबोधित किया। प्रतिनिधियों के विरोध के कारण एक नहीं, दो बार सभा को स्थगित करना पड़ा। मगर जिन्ना टस से मस नहीं हुए। उनका तर्क था कि ‘महात्मा’ शब्द हिंदू अध्यात्म से जुड़ा है, इसलिए यह राजनीति में धर्म का समावेश है। यदि यह तर्क मान लिया जाता, तब भारत का संपूर्ण दर्शन सांप्रदायिक बन जाएगा, क्योंकि, यहां दर्शन और अध्यात्म के बीच रेखा खींचना नामुमकिन है। याज्ञवल्क्य से लेकर महावीर-बुद्ध-नानक सभी के

अपनी पुस्तक ‘माइनॉरिटीज इन इंडिया’ (1948) में पूछा है कि वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराणों आदि को हटा देने से भारत क्या रह जाएगा?

भारतीय दर्शन और पंथनिरपेक्षता का सवाल

– कांग्रेस को वंदे मातरम् पर आपत्ति है, तो शक और विक्रम संवत का भी हिंदू इतिहास है। तो क्या उसे भी वे खारिज कर देंगे? संविधान सदन, संसद भवन, सेना मुख्यालय, जीवन बीमा, सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि का ध्येय वाक्य उन्हीं दार्शनिक ग्रंथों से लिया गया है, तो क्या वे हिंदू पूर्वाग्रह का बहुमतवाद हैं। सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ महाभारत से लिया गया है, तो गणतंत्र का ध्येय वाक्य ‘सत्यमेव जयते’ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। रवींद्रनाथ ठाकुर के ‘गोरा’ उपन्यास में गोरा और

सुचरिता के बीच संवाद में भारत और धर्म की भारतीय अवधारणा सामने आती है। तब तो वह भी उन्हें स्वीकार नहीं होगा! कुछ वर्ष पूर्व जब ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ मनाने की बात हुई, तब भी योग की हिंदू उत्पत्ति तलाशी गई और इसका विरोध हुआ। कांग्रेस की परिभाषा के अनुसार, भारत का अहिंदूकरण ही पंथनिरपेक्षता है। ‘वंदे मातरम्’ एक सकारात्मक और प्रेरणादायक गीत है, जिसे गाकर, सुनकर या पढ़कर देशभक्ति जीवंत हो जाती है। महर्षि अरविंद और लाला लाजपत राय ने क्रमशः कलकत्ता और लाहौर में ‘वंदे मातरम्’ नाम से अखबार शुरू किया। कांग्रेस के साथ त्रासदी है कि उसका विचार यथार्थ से हमेशा दूर रहा है। आज की कांग्रेस में विचारों की बहुलता नहीं है। कोई संपूर्णानंद या केएम मुंशी आज कांग्रेस के पास नहीं हैं। यह वैचारिक बहुलता सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के क्रम में देखने को मिली थी। तब पंडित नेहरू इसके विरोध में थे, तो राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसकी अगुआई कर रहे थे।

सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर बहस – जब भी अपने इतिहास, विरासत, नायकों की खोज या उनकी स्मृति को बनाए रखने का कोई उपक्रम बनता है, उसे धर्मनिरपेक्षता पर सवाल कह दिया जाता है। इसका एक उदाहरण कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक के निर्माण से जुड़ा है। एकनाथ रणडे के प्रयास के विरुद्ध केरल से दिल्ली तक विरोध जताया गया। भारत अपने सांस्कृतिक उत्थान के दौर में प्रवेश कर रहा है। मगर पुरानी सोच और पुरानी ताकत अपने बौद्धिक आधिपत्य को टूटते नहीं देख पा रही है। कांग्रेस और उसके बुद्धिजीवी मित्र छद्म पंथनिरपेक्षता के आधार पर भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक समय लोकमान्य तिलक के गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव को मुस्लिम विरोधी घोषित किया गया, उसी को आज वंदे मातरम् को लेकर दोहराया जा रहा है। (यह लेखक के अपने विचार हैं)

संक्षिप्त समाचार

रसोई पर लगातार महंगाई की मार

नई दिल्ली, एजेंसी। खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई के बीच अब प्याज के दाम ने भी आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ना



शुरू कर दिया है। पिछले करीब दो सप्ताह में दिल्ली के खुदरा बाजारों में प्याज की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। अगस्त की शुरुआत में जहां प्याज 25 से 30 रुपये किलो बिक रही थी, वहीं अब इसका खुदरा भाव 60 से 70 रुपये किलो तक पहुंच गया है। आजादपुर मंडी में अच्छी क्वालिटी की प्याज करीब 50 रुपये किलो तक पहुंच गई है, जबकि समान्य गुणवत्ता की प्याज 40 से 45 रुपये किलो के आसपास बिक रही है। आजादपुर मंडी के प्याज व्यापारी श्रीकांत मिश्रा के मुताबिक, इसका एक बड़ा कारण मौसम की मार है। अप्रैल में हुई बारिश से महाराष्ट्र नासिक और मध्य प्रदेश समेत प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों में फसल को नुकसान पहुंचा था। वहीं नई फसल आने में समय लगेगा। व्यापारियों और फसल विशेषज्ञों के अनुसार, मौनसून की अनिश्चितता के कारण खरीफ प्याज की बोआई में देरी, रबी प्याज की कमजोर आवक और सरकारी खरीद का लक्ष्य से काफी कम रह जाना प्रमुख कारण हैं। जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र की नासिक मंडी में भी करीब एक महीने के दौरान प्याज की कीमत में लगभग 76 प्रतिशत तक की बढ़तरी दर्ज की गई है। कुछ राज्यों में थोक भाव में करीब दोगुनी वृद्धि की बात सामने आई है। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब बफर स्टॉक जारी करने की तैयारी में है। खासतौर पर उन शहरों में बफर प्याज उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा सकता है, जहां खुदरा कीमतों में तेजी ज्यादा है। हालांकि सवाल यह है कि सीमित बफर स्टॉक से बाजार को कितनी राहत मिल पाएगी। श्रीकांत शर्मा का कहना है कि इस साल प्याज का बफर स्टॉक घटकर लगभग डेढ़ लाख टन रह गया है। ऐसे में नई फसल की आवक तक आने वाला करीब डेढ़ महीना उपभोक्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गाजीपुर मंडी में सब्जियों के थोक विक्रेता विनोद चैधरी ने बताया कि प्याज के अलावा फूल गोभी और मटर 100 का रेट पर कर चुके है, मंडी में अदरक भी 50 से 60 रुपये थोक में बिक रहा है, इसी तरीके से देसी खीरे का रेट भी 25 से 30 रुपये तक का पहुंच गया है।

महंगी हुई चीनी तो लोगों ने कम किया इस्तेमाल, सर्वे में बता दी अपने दिल की बात

नई दिल्ली, एजेंसी। इस महीने भारतीय रसोई में चीनी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 20 जुलाई 2026 को देशभर में चीनी की औसत कीमत 48.18 रुपये प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त 2026 तक बढ़कर 55.70 रुपये हो गई। सरकार ने 30 सितंबर तक चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट की इजाजत दी है। इस बीच चीनी की बढ़ती कीमतों पर सर्वे किया है। इसमें लोगों से चीनी महंगी होने पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई। मसलन चीनी महंगी होने के कारण उनकी खपत पर क्या असर हुआ और वे रोजाना कितनी चीनी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें यह देखने में आया की चीनी महंगी होने से लोगों ने इसका इस्तेमाल कर दिया है।

हमारा सबसे कठिन दिन वो था, दो गृहिणियों ने कॉर्पोरेट डिग्री वालों को छोड़ा पीछे, खड़ा किया अपना ब्रांड

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार की दो गृहिणियों ने कमाल कर दिया है। बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड के इन्होंने एक सफल ब्रांड बना खाला है। इनके नाम नीतू



यादव और गीता सिंह हैं। दोनों की उम्र 50 साल से ज्यादा है। अपने तीन दशकों के घरेलू अनुभव के दम पर उन्होंने अपने स्टार्टअप की नींव रखी। इसका नाम द ठेकुआ कंपनी है। यह डी2डी स्टार्टअप बेंगलुरु से ऑपरेट हो रहा है। मिथिला के पारंपरिक स्वाद ठेकुआ को यह अल्ट्रा-प्रोसेस्ड बिरिकट के स्वस्थ विकल्प के रूप में देशभर के घरों तक पहुंचाने में लगा है। आइए, यहां नीतू यादव और गीता सिंह की

सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। बिहार, यूपी और झारखंड में सदियों से ठेकुआ खाया जाता रहा है। लेकिन, पिछले कुछ दशकों में यह छट के कारण ज्यादा



प्रचलित हुआ। देश में रोजमर्रा के स्नैक्स पर प्रोसेस्ड बिरिकट का राज है। पाम ऑयल और मैदे से बने इन बिरिकट के बढ़ते प्रभाव को देखकर नीतू यादव और गीता सिंह को आइडिया आया। उन्होंने ठेकुआ को स्नैक्स में तब्दील करने का फैसला किया। नवंबर 2025 में छठ पूजा के दौरान दोनों ने बिना किसी पेड विज्ञापन के केवल वर्ड-ऑफ-माउथ के आधार पर इसका पायलट परीक्षण किया। अनजान ग्राहकों से

मिले बेहतरीन रेसर्पोन्स और बार-बार मिलने वाले ऑर्डरों ने यह साबित कर दिया कि लोग साफ-सुथरे और पारंपरिक स्नैक्स की तलाश में हैं। इसके बाद मई 2026 को कंपनी को औपचारिक रूप से रजिस्टर्ड किया गया। नीतू और गीता के स्टार्टअप की खासियत इसकी शुद्धता और बनाने का पारंपरिक तरीका है। बाजार में मिलने वाले अन्य बेकड आइटम्स के उलट यहां हर बैच को 100 प्रतिशत शुद्ध देसी घी, साबुत गेहूं के आटे, प्राकृतिक गुड़ या चीनी और सुखे नारियल से तैयार किया जाता है। स्वाद और बनावट को असली बनाए रखने के लिए मिट्टी और लकड़ी के पारंपरिक सांचों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किए बिना भी इन ठेकुओं की शेल्फ लाइफ 90 दिनों की होती है। वर्तमान में कंपनी गुड़, चीनी और ड्राई फ्रुट्स के कॉम्बिनेशन में 4 मुख्य वेरिएंट्स पेश कर रही है। घरेलू स्तर से कमर्शियल स्कूल पर जाने का सफर आसान नहीं था। बिना किसी ऑटोमेटेड मशीनरी के एक ही दिन में 25 किलो ठेकुआ हाथ से तैयार करने डिलीवर करना फाउंडर्स के लिए सबसे बड़ी ऑपरेशनल चुनौती थी। इसके अलावा क्रूरियर डिलीवरी के दौरान इन्हें टूटने से बचाने के लिए पैकेजिंग को मजबूत बनाना भी बड़ा टास्क रहा।

छत्तीसगढ़ में सोना खोजने उतरी अनिल अग्रवाल की वेदांता, भारत में पहली बार हो रहा पोर्टेबल रिग का इस्तेमाल

नई दिल्ली, एजेंसी। दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने देश में सोने की खोज की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने सोने के साथ-साथ निकल और क्रोमियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स तथा प्लेटिनम रूप के एलिमेंट्स को खोजने के लिए एक हाई स्पीड हाइड्रोस्टैटिक पोर्टेबल रिग कमीशन किया है। छत्तीसगढ़ में दो प्रोजेक्ट में इस इक्विपमेंट को तैनात किया गया है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यह देश का पहला हाई-स्पीड हाइड्रोस्टैटिक पोर्टेबल रिग है और इसे मुश्किल इलाकों में एक्सप्लोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह 1,000 मीटर की गहराई तक खुदाई कर सकता है। साथ ही इसकी मदद से उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में कम समय लगता है। वेदांता ने कहा कि हाई-स्पीड हाइड्रोस्टैटिक पोर्टेबल रिग की तैनाती का मकसद मिनरल रिजर्व की खोज में तेजी लाना है। साथ ही इसे सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता भी बेहतर होगी। कंपनी का कहना है कि उसे 10 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक मिले हैं। इनमें सोना, मैंगनीज, कॉपर, निकिल-क्रोमियम, टंगस्टन, ग्रेफाइट, वैनेडियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और पोटाश मिलने की संभावना है। इनमें से पांच ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है। साथ ही कंपनी को आंध्र प्रदेश के पुत्रम मैंगनीज ब्लॉक में भी सफल बिड घोषित किया गया है। कंपनी का कहना है कि 2030 तक क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल डिमांड तिगुना होने की संभावना है। 2040 तक इसके सालाना 40 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।

सिर्फ 1000 निवेश और 8.2 प्रतिशत का दमदार रिटर्न!

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर आप पैसों की बचत की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए किसी खास उम्र के पड़ाव की जरूरत नहीं है। आप किसी भी समय में अपनी बचत की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए सरकारी से लेकर प्राइवेट तक कई सारी योजनाएं हैं। इस बीच हम देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए एक खास बचत योजना की बात कर रहे हैं, यह काफी पसंद भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत केवल 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। इतना ही नहीं इसके निवेश पर 8.2 फीसदी की ब्याज दर से सरकार रिटर्न भी देती है। सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम हम यहां सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम की बात कर रहे हैं, जो एक पोस्ट ऑफिस जमा योजना भी है। इस खाता को आप डाकघर या अपने किसी नजदीकी अधिकृत बैंक में भी खोल सकते हैं। इस योजना को सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही बनाया है। इसमें आप कम से कम 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं, योजना में अधिकतम निवेश की राशि की सीमा 30 लाख रुपये तक है।

इस योजना में जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती के पात्र हैं। योजना में जमा राशि पर सरकार 8.2 फीसदी का सालाना ब्याज देती है, जिसका भुगतान हर तीन महीने (तिमाही आधार) पर सीधे खाते में होता है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (सीनियर



सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम) को खोलने की तारीख से 5 साल का समय समाप्त होने के बाद कभी भी बंद किया जा सकता है। मतलब कि इस योजना के तहत जमा राशि केवल पांच साल में ही मैच्योर हो जाती है। हालांकि, इसे आगे तीन वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उसके लिए फॉर्म भी सबमिट करना होता है। एक्सटेंशन केवल एक बार ही किया जा सकता है। अब बात वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की पात्रता की करते हैं।

105 प्रतिशत के पार पहुंचा जीएमपी, आईपीओ में पहले ही दिन दोगुना हो सकता है पैसा

नई दिल्ली, एजेंसी। टेम्पसेंस इंस्ट्रुमेंट्स (इंडिया) के शेयर ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम इसके आईपीओ प्राइस को भी पार कर गया है। टेम्पसेंस इंस्ट्रुमेंट्स (इंडिया) के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़कर 105 पसेंट के पार पहुंच गया है। कंपनी के शेयरों के मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम और दूसरे ट्रेंड्स को देखें तो निवेशकों का पैसा पहले ही दिन दोगुना हो सकता है। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट मंगलवार 25 अगस्त को फाइनल हो सकता है। टेम्पसेंस इंस्ट्रुमेंट्स (इंडिया) की शुरुआत साल 1990 में हुई है। टेम्पसेंस इंस्ट्रुमेंट्स (इंडिया) एक थर्मल इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज्ड केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।



कंपनी कस्टमाइज्ड टेम्प्रेचर सेंसिंग और स्पेशलाइज्ड केबल्स की डिजाइनिंग सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस और मैन्युफैक्चरिंग करती है।

184 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का आईपीओ

टेम्पसेंस इंस्ट्रुमेंट्स (इंडिया) का आईपीओ टोटल 184.22 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 61 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, एंज्लोयीज का कोटा 124.95 गुना सब्सक्राइब हुआ। टेम्पसेंस इंस्ट्रुमेंट्स (इंडिया) के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स कैटेगरी में 314.44 गुना दांव लगा है।

सरकार के एक फैसले से हिंदुस्तान कॉपर का शेयर धड़ाम

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का शेयर मंगलवार को बाजार खुलते ही गिर गया। इस शेयर में यह गिरावट सरकार के उस फैसले के बाद आई है, जिसमें सरकार ने कहा कि वह इस कंपनी से अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार ने यह फैसला विनिवेश के जरिए फंड जुटाने के उद्देश्य से लिया है। हिंदुस्तान कॉपर का शेयर सोमवार को 573.55 रुपये पर बंद हुआ था। मंगलवार को यह करीब 6 फीसदी की गिरावट के साथ 540 रुपये पर खुला। बाद में इसने मामूली बढ़त बनाई, लेकिन यह बहुत देर टिकी नहीं रही। 9-30 बजे यह शेयर 6.20 प्रतिशत फीसदी की गिरावट के साथ 538 रुपये पर कारोबार कर रहा था। एक समय यह शेयर 534.05 रुपये तक पहुंच गया था।

क्या है सरकार का प्लान

सरकार में बिक्री पेशकश (ओफएएस) के जरिए 6 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचेगी। इसके लिए न्यूनतम

कीमत 514 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। इस बिक्री से सरकार 3000



करोड़ रुपये जुटाएगी। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरुणीश चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत सरकार हिंदुस्तान कॉपर में तीन प्रतिशत हिस्सेदारी ओफएएस के जरिए बेचेगी। मांग अधिक रहने पर अतिरिक्त तीन प्रतिशत



पेशकश का 10 प्रतिशत हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा पात्र कर्मचारियों के लिए 25,000 शेयर रखे गए हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश के जरिये 52,716 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

रिटर्न के मामले में हिंदुस्तान कॉपर का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। कंपनी ने

रिवगी इंस्टामार्ट और बिग बास्केट का फूड लाइसेंस सरस्पेंड



अगला आदेश कब आएगा: विभाग ने कहा कि इस ऑर्डर के कंप्लायेंस रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद एक

उल्लंघन होने पर लागू कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई से पहले हुई जांच, रिस्पांस संतोषजनक नहीं

ऐसा नहीं है कि फूड सेफ्टी विभाग ने यह कार्रवाई आनन-फानन में की। इस कार्रवाई से पहले फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि धतूरा के लिए और बीज इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर का उपयोग करके स्टोर किया गया था और उसे बेचा जा रहा था। उसके बाद मामले की सुनवाई बीते 24 अगस्त को हुई। इस दौरान संबंधित प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधि भी शुरु हुए थे। इन कंपनियों के रिस्पांस को विभाग ने संतोषजनक नहीं माना। विभाग ने कहा कि धतूरा के फलों और बीजों की विषाक्त प्रकृति है। इससे पब्लिक हेल्थ को खतरा है। इसलिए अगले आदेश तक के लिए इन पदार्थों की बिक्री को सरस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही ऐसे प्रोडक्ट की स्पलाई करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया।

सेपरेट ऑर्डर पारित किया जाएगा। साथ ही कहा कि स 'ब' िध त प्लेट फॉर्म्स को निर्देशों का पालन करना होगा। आदेश का कोई भी

इंस्पेक्शन में तय्य मिला

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने इंस्पेक्शन के दौरान धतूरा के के फल और बीज के पैकेट बरामद किए। उन पैकेटों पर फूड रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित थे। ये प्रोडक्ट्स एक गोदाम में भी पाए गए और ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बेचे जा वितरित किए जा रहे थे। प्राधिकरण का कहना है कि धतूरा के बीच में विषैले गुण पाए जाते हैं और इसका खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करना हानिकारक हो सकता है। इससे स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम हो सकता है। साथ ही इसकी बिक्री गैरकानूनी भी है। प्रोसिडिंग्स के मुताबिक अमेजन ने तो विभाग द्वारा जारी नोटिस का कोई जवाब ही नहीं दिया। वहीं रिवगी इंस्टामार्ट ने नोटिस के बाद की गई कार्रवाई का विवरण देने के लिए और समय मांगा।



महिला टी-20 एशिया कप 2026 का आगाज 28 अगस्त से

भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर बोली हरमनप्रीत कौर, 'ऐसा दबाव कहीं और महसूस नहीं होता'

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एसीसी महिला टी20 एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले बड़ा बयान दिया है। हरमनप्रीत ने स्वीकार किया कि भारत-पाकिस्तान मैच का दबाव किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से बिल्कुल अलग होता है। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि खिलाड़ियों को नतीजे की चिंता करने के बजाय अपनी योजना, रूटीन और टीम की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। महिला टी20 एशिया कप 2026 का आगाज 28 अगस्त से होगा, जबकि भारत और पाकिस्तान की टीमें 5 सितंबर को ग्रुप स्टेज के हाई-वोल्टेज मुकाबले में आमने-सामने होंगी।
'मैच जीतना है' का दबाव नहीं लेना

‘इस मुकाबले की अहमियत अन्य बड़े अंतरराष्ट्रीय मैचों से अलग होती’
हरमनप्रीत कौर ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले में खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव काफी ज्यादा होता है और इस मुकाबले की अहमियत अन्य बड़े अंतरराष्ट्रीय मैचों से अलग होती है। हरमनप्रीत ने मीडिया से कहा, 'इसमें कोई शक नहीं कि यह एक हाई-प्रेशर गेम है और एक खिलाड़ी के तौर पर आपको कई चीजों से निपटना पड़ता है। हम लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन भारत-पाकिस्तान मैच में जिस तरह का दबाव होता है, वैसा दबाव कहीं और महसूस नहीं होता।'

कप्तान के तौर पर चीजों को सरल रखना चाहती हैं हरमनप्रीत
भारतीय कप्तान ने कहा कि ऐसे मुकाबलों में अतिरिक्त दबाव लेने के बजाय खिलाड़ियों के लिए अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह कप्तान और खिलाड़ी, दोनों भूमिकाओं में चीजों को आसान और सरल रखने की कोशिश करती हैं। हरमनप्रीत ने कहा, 'एक कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर मैं चीजों को बहुत सरल और आसान रखने की कोशिश करती हूं। अपने लक्ष्य और अपनी रूटीन पर होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी रूटीन का सही तरीके से पालन करते हैं तो नतीजे जरूर मिलते हैं।'



सिनसिनाटी ओपन

कोको गॉफ ने दूसरी बार जीता खिताब, पुरुष वर्ग में आर्थर फिल्स चैंपियन बने



मेसन (अमेरिका) (एजेंसी)। कोको गॉफ ने हमवतन अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला को सीधे सेटों में हराकर सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब दूसरी बार अपने नाम कर लिया। वहीं, पुरुष एकल के फाइनल में फ्रांस के आर्थर फिल्स ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर अपने करियर का पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीत लिया।

गॉफ ने पेगुला को सीधे सेटों में हराया – महिला एकल के फाइनल में कोको गॉफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जेसिका पेगुला को 6-2, 6-4 से मात दी। गॉफ ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और पहले सेट में 5-0 की मजबूत बढ़त हासिल करने के बाद उसे 6-2 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में पेगुला ने वापसी करने की कोशिश की और स्कोर को 5-4 तक पहुंचा दिया। हालांकि, गॉफ ने दबाव में शानदार संयम दिखाया और मैच जीतकर सिनसिनाटी में अपना दूसरा महिला एकल खिताब जीत लिया। गॉफ ने मुकाबले के दौरान मिले छह में से पांच ब्रेक प्वाइंट को भुनाया।

बालाजी-चंद्रशेखर ने कानकुन टेनिस ओपन जीता

● **फाइनल में मैक्सिको और बेलारूस की जोड़ी को हराया, करीब 9.5 लाख मिले**



मैक्सिको (एजेंसी)। भारत के एन. श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने मैक्सिको में खेले गए कानकुन कट्टी टेनिस ओपन का डबल्स खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मैक्सिको के मिगुएल एंजेल रेयस-वरेला और बेलारूस के इवान लुट्यारेविच को 6-3, 7-6(4) से हराया। इस जीत के साथ बालाजी और अनिरुद्ध की 125-125 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रैंकिंग पॉइंट्स और 9,900 डॉलर (करीब 9.5 लाख रुपए) की इनामी राशि मिली।

पहले सेट में 6-3 से जीते, दूसरा टाईब्रेकर में –फाइनल के पहले सेट में दोनों जोड़ियों के बीच मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन भारतीय जोड़ी ने अहम मौकों पर बढ़त बनाते हुए सेट 6-3 से अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने पहली सर्विस पर 68 प्रतिशत और दूसरी सर्विस पर 81 प्रतिशत अंक जीते। बालाजी और अनिरुद्ध ने टाईब्रेकर में 7-4 से जीत दर्ज की और 7-6(4) से दूसरा सेट अपने नाम करते हुए खिताब जीत लिया।

पूर्व वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बच्चों के यौन शोषण में दोषी

1993 से 2010 के बीच लड़की और लड़के से दुर्व्यवहार; स्नूकर संस्था ने सदस्यता खत्म की



ग्लासगो (एजेंसी)। पूर्व वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन ग्रेम डॉट को बच्चों के यौन शोषण के दो मामलों में दोषी पाया गया है। 149 साल के डॉट के खिलाफ ग्लासगो हाई कोर्ट में पांच दिन तक सुनवाई चली। ज्युरी ने उन्हें 1993 से 1996 के बीच एक लड़की और 2006 से 2010 के बीच एक लड़के के साथ किए गए यौन दुर्व्यवहार से जुड़े दोनों मामलों में दोषी माना। अदालत ने डॉट की सजा पर फैसला अगली सुनवाई में करने का आदेश दिया है। यह सुनवाई 29 सितंबर 2026 को एंडिनबर्ग में होगी। तब तक डॉट हिरासत में रहेंगे। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि डॉट ने 1990 के दशक में एक स्कूली लड़की के साथ कई बार अनुचित व्यवहार किया। अब 40 की उम्र में पहुंच चुकी महिला ने आरोप लगाया कि डॉट ने उसे गलत तरीके से छुआ और उसे यौन गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की। महिला ने अदालत में बताया कि इन घटनाओं से वह डर गई और सदमे में थी। डॉट ने उसे एक टेडी बियर भी दिया था। पुलिस ने 2001 में इन आरोपों को लेकर डॉट से संपर्क किया था, लेकिन उस समय कोई चार्ज नहीं लगाया गया। दूसरे मामले में एक लड़के ने अदालत को बताया कि डॉट ने 2006 के बाद उसका यौन शोषण किया। उस समय उसकी उम्र करीब 8 साल थी। उसने अदालत में डॉट पर बाथरूम, कार और अन्य जगहों पर अनुचित तरीके से छुने और यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। उसने यह भी बताया कि डॉट उसे चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक और एक बार 50 पाउंड दंकर 'इनाम' देता था।

प्रज्ञाननंदा ग्रैंड चेस टूर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे

जर्मनी के कीमर को 19-9 से हराया; अब डिफेंडिंग चैंपियन कारुआना से मुकाबला



सेंट लुइस (एजेंसी)। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञाननंदा ग्रैंड चेस टूर (जीसीटी) 2026 के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में प्रज्ञाननंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विसेंट कीमर को 19-9 से हराया। प्रज्ञाननंदा ने क्लासिकल और रैपिड गेम के बाद ही फाइनल में जगह पक्की कर ली थी। इसके बाद खेले गए तीन ब्लिट्ज गेम हारने के बावजूद उनके कुल स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा। अब 25 अगस्त को खिताबी मुकाबले में प्रज्ञाननंदा का सामना डिफेंडिंग चैंपियन अमेरिका के फैबियानो कारुआना से होगा।

तीन गेम बाकी रहते ही फाइनल पक्का किया – प्रज्ञाननंदा ने सेमीफाइनल के दूसरे क्लासिकल गेम में कीमर को हराकर 9-3 की बढ़त हासिल की। इसके बाद रैपिड गेम्स में भी उन्होंने बढ़त बनाए रखी। रैपिड मुकाबलों के बाद प्रज्ञाननंदा ने 3 गेम बाकी रहते ही सेमीफाइनल अपने नाम कर लिया। यानी ब्लिट्ज के नतीजे उनके फाइनल में पहुंचने की स्थिति को बदल नहीं सकते थे। इसके बाद चार ब्लिट्ज गेम खेले गए। प्रज्ञाननंदा ने पहले ब्लिट्ज गेम में हार की स्थिति से वापसी करते हुए जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद कीमर ने लगातार तीन ब्लिट्ज गेम जीत लिए। इसके बावजूद सेमीफाइनल का कुल स्कोर 19-9 प्रज्ञाननंदा के पक्ष में रहा।

सरकारी अस्पताल होंगे डिजिटल कमांड सेंटर से होगी मॉनिटरिंग

रांची, नवबिहार टाइम्स संवाददाता। झारखंड के सभी सरकारी अस्पताल अब डिजिटल निगरानी व्यवस्था से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम के तहत सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल डैशबोर्ड स्थापित करने को लेकर मंगलवार को रॉडिक कंपनी के साथ स्वास्थ्य विभाग का एमओयू हुआ। इसके बाद राज्यभर के अस्पतालों की गतिविधियों की निगरानी केंद्रीय कमांड सेंटर से की जा सकेगी।

इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। अस्पतालों को तकनीक से जोड़ने का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। एमओयू के

राज्यभर के अस्पतालों की गतिविधियों की निगरानी केंद्रीय कमांड सेंटर से की जा सकेगी

तहत अस्पतालों में सीसीटीवी और डैशबोर्ड आधारित व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे अस्पतालों में व्यवस्थाओं की स्थिति पर मुख्यालय स्तर से नजर रखी जा सकेगी। जरूरत के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तत्काल जानकारी उपलब्ध होगी और समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई भी संभव हो सकेगी।

स्वास्थ्य विभाग के इस कदम से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, अस्पताल की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली की निगरानी में तकनीक की भूमिका बढ़ेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही को मजबूत करना है।

संक्षिप्त समाचार

हथियार बताओ, इनाम पाओ: पलामू में अपराधियों के अवैध हथियार पुलिस के निशाने पर

मेदिनीनगर, पलामू/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। नक्सलियों के हथियारों की सूचना पर इनाम देने की तर्ज पर अब पलामू पुलिस ने अपराधियों के अवैध हथियारों को भी निशाने पर लिया है। पुलिस ने हथियारों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है। ऑटोमेटिक हथियार की सूचना देने पर 20 हजार रुपये से अधिक, पिस्टल की जानकारी पर 15 हजार और देसी कट्टा बरामद कराने वाली सूचना पर पांच हजार रुपये तक इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले की पहचान और इनाम की राशि गोपनीय रखी जाएगी। पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि आर्स एक्ट से जुड़े मामलों की समीक्षा में जिले में 851 आरोपी विहित हुए हैं। अवैध हथियारों के खिलाफ चल रहे अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए यह पहल की गई है। मई 2026 तक जिले में 48 हथियारों की जानकारी मिली है। पुलिस ने जुलाई-अगस्त में ऑपरेशन सफाया के तहत 30 से अधिक हथियार बरामद किए हैं। 2023 से अब तक नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ अभियान में 300 से अधिक हथियार जब्त किए जा चुके हैं। इनमें देसी कट्टे सबसे अधिक हैं। वर्ष 2023 में 56,2024 में 48,2025 में 47 और 2026 में अगस्त के पहले सप्ताह तक 35 से अधिक हथियार बरामद किए गए हैं। सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारियों को अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया है।

ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत
हुसैनबाद, पलामू/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। हुसैनबाद थाना क्षेत्र के बरडीहा गांव के पास सोमवार देर शाम अज्ञात ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 60 वर्षीय जयराम पासवान की मौत हो गयी। वह बिशनपुर गांव के निवासी थे। परिजनों के अनुसार जयराम बाइक से हुसैनबाद बाजार जा रहे थे। इसी दौरान बरडीहा के पास पीछे से आ रहे अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें हुसैनबाद अमृतमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में मेदनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल पुलिस चौकी के पुलिस पदाधिकारी व जवान विकास कुमार और महेंद्र कुमार पहुंचे। पुलिस ने परिजनों से जानकारी लेने के बाद शव का इन्वेस्ट कर पोस्टमॉर्म के लिए भेज दिया। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

डिजनीलैंड मेले में बाल श्रम का खेल, सात बच्चे मुक्त
मेदिनीनगर, पलामू/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। शहर के शिवाजी मैदान में लगे डिजनीलैंड मेले में बाल श्रम कराए जाने की सूचना पर मंगलवार को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और श्रम विभाग की टीम ने छापामारी की। कार्रवाई के दौरान मेले में विभिन्न कामों में लगाए गए सात बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।टीम की अचानक हुई कार्रवाई से मेला परिसर में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने अलग-अलग स्टॉल और काम करने वाले स्थानों की जांच की। इस दौरान कम उम्र के बच्चों से काम कराए जाने का मामला सामने आया। टीम ने तत्काल बच्चों को वहां से मुक्त कराया और उन्हें आवश्यक प्रक्रिया के तहत अपने संरक्षण में लिया। अधिकारियों के अनुसार, बच्चों से श्रम कराना कानूनन अपराध है। इसके बावजूद मेले जैसे सार्वजनिक आयोजन में बच्चों को काम पर लगाए जाने से बाल श्रम रोकने के सरकारी दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्रवाई के बाद संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की तैयारी है।

घर में नहीं, अब सरकारी भवन में सजेगा आंगनबाड़ी केंद्र
हुसैनबाद, पलामू/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। देवरी कला पंचायत अंतर्गत पहाड़ी गांव में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया गया। देवरी कला पंचायत समिति सदस्य अजीत कुमार सिंह ने फीता काटकर केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व मुखिया रामाशंकर चौधरी, पूर्व मुखिया सह राजद के हुसैनबाद प्रखंड अध्यक्ष सुदेश्वर राम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। उपायुक्त एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के निर्देशानुसार अब आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन सरकारी भवन में ही किया जाएगा। इससे पहले केंद्र का संचालन सेविका द्वारा अपने निजी आवास से किया जा रहा था। नवनिर्मित भवन उपलब्ध होने के बाद नवचयनित सेविका संगीता कुमारी (देवी) ने उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करते हुए केंद्र को सरकारी भवन में संचालित करने का निर्णय लिया।

शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डीसी ने दिये आवश्यक निर्देश

मेदिनीनगर, पलामू, नवबिहार टाइम्स संवाददाता। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में छत्र एवं शिक्षक उपस्थिति, छत्र नामांकन, आधार एवं अडहअअफ शुन्य नामांकन वाले विद्यालय, रेल परफॉर्मेंस, एटउ पुनर्गठन, शिक्षक मॉड्यूल, एवउ प्री-मैट्रिक छत्रवृत्ति सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई।

छत्र उपस्थिति में सुधार पर जोर

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जुलाई 2026 में पलामू में छत्रों की औसत उपस्थिति 75.5 प्रतिशत रही, जबकि शिक्षक



उपस्थिति 88.5 प्रतिशत दर्ज की गई। उपायुक्त श्री शेखावत ने छत्र उपस्थिति में और सुधार लाने के लिए विद्यालय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग एवं कम उपस्थिति वाले विद्यालयों के कारणों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई

महिला सुरक्षा को नई मजबूती: टाउन महिला थाना के नवनिर्मित भवन का एसपी ने किया उद्घाटन

मेदिनीनगर, पलामू/ नवबिहार टाइम्स संवाददाता। टाउन थाना परिसर में नवनिर्मित टाउन महिला थाना के नए भवन का उद्घाटन सोमवार को पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने किया। नए भवन के शुरू होने से महिला संबंधी मामलों के निष्पादन में तेजी आने के साथ पीड़ित महिलाओं को बेहतर और सुविधाजनक माहौल मिलने की उम्मीद है।

उद्घाटन के अवसर पर एसडीपीओ राजेश यादव, प्रभारी मेजर सुरेश राम, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार, सार्जेंट मेजर विमल चंद्रवंशी, महिला थाना प्रभारी पार्वती कुमारी समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। नए भवन में महिला संबंधी शिकायतों और मामलों के निष्पादन के लिए



बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी। इससे पीड़ित महिलाओं को अपनी समस्याएं पुलिस के समक्ष रखने में अधिक

सुविधा मिलेगी। पुलिस अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि नए भवन के माध्यम से महिला सुरक्षा

और महिला संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक किशोर कौशल ने मंगलवार को बरवाडीह थाना का किया निरीक्षण

थाना परिसर पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया

मेदिनगर, पलामू, नवबिहार टाइम्स संवाददाता। निरीक्षण के दौरान पुलिस उप-महानिरीक्षक श्री किशोर कौशल ने थाना परिसर, कार्यालय एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने थाना में संधारित अभिलेखों, लॉबित मामलों तथा पुलिसिंग से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, लॉबित मामलों के त्वरित निष्पादन तथा आम जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही क्षेत्र में नियमित



गश्ती एवं प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने की बात कही। इस दौरान उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को उन्होंने अनुशासन, पारदर्शिता और टीम भावना के साथ कार्य करने की नसीहत दी तथा बेहतर पुलिसिंग के माध्यम से

जनता का विश्वास और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। निरीक्षण के दौरान एस.डी.पी.ओ. श्री बिरेन्द्र कुमार राम, थाना प्रभारी पुष्पअङ्गनिष्ठ अनुराग कुमार एवं अन्य पदस्थापित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मो. जावेद हुसैन

की अध्यक्षता में राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक

एसआइआर के तहत नोटिस एवं सुनवाई प्रक्रिया एवं निर्धारित दस्तावेजों की दी गई जानकारी

खूंटी, नवबिहार टाइम्स संवाददाता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्क्रम) के अंतर्गत नोटिस एवं सुनवाई की प्रक्रिया, दावा-आपत्ति के निस्तारण तथा मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने को लेकर आवश्यक जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि नोटिस एवं दावा-आपत्तियों के निष्पादन के चरण में बीएलओ द्वारा नो-मैपिंग, तार्किक विसंगति तथा अन्य संबंधित सूचियों में शामिल मतदाताओं को नोटिस उपलब्ध कराया जाएगा। नोटिस प्राप्त होने के बाद संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दावा-आपत्ति की अवधि 5 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक निर्धारित है तथा प्राप्त दावों एवं



आपत्तियों का निस्तारण 14 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। साथ ही पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, प्रविष्टियों में आवश्यक सुधार तथा फॉर्म-8 के माध्यम से नाम स्थानांतरण की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। बैठक में राजनीतिक प्रतिनिधियों को यह भी बताया गया कि स्क्रमके अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों की सार्वजनिक सूची में केंद्र/राज्य सरकार अथवा ढव के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र/ढवड, 01 जुलाई 1987 से पूर्व

सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, छहठ अथवा ढव द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र या दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का मैट्रिक्युलेशन अथवा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, डडउ/रड/खड अथवा अन्य जाति प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो वहां उषड, राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान

आवंटन प्रमाण-पत्र शामिल हैं। बैठक में एक परिवार अथवा एक ही घर के मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र को मतदाता सूची में दर्ज करने की दिशा में किए गए निर्देशों से भी अवगत कराया गया। राजनीतिक प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे पात्र नागरिकों को सही जानकारी उपलब्ध कराने एवं आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत कराने में सहयोग करें।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने कहा कि स्क्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। किसी भी पात्र भारतीय नागरिक को छवराणे की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मी आवश्यक सहयोग के लिए तत्पर हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा सहायता के लिए निर्वाचन आयोग के टेल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

एसपी ऋषभ गर्ग ने 53 गुम मोबाइल वास्तविक धारकों को सौंपा



खूंटी, नवबिहार टाइम्स संवाददाता। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापक- 1227/टी.एस., दिनांक- 22.07.2026 के आलोक में तथा पुलिस अधीक्षक महोदय, खूंटी के निर्देशानुसार हमिशन मुस्कानह के तहत जिले में गुम-चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के क्रम में खूंटी जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम-चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु सभी थाना प्रभारियों एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारियों-कर्मियों द्वारा समन्वित रूप से कार्रवाई करते हुए सीआईआरपी सेंटर इक्वुपमेंट रजिस्टर पोर्टल एवं अन्य उपलब्ध तकनीकी माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया गया। इसी क्रम में बरामद किए गए कुल 53 मोबाइल फोन को मंगलवार को पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग द्वारा उनके वास्तविक धारकों को विधिवत सुपुर्द किया गया। अपने गुम हुए मोबाइल फोन वापस प्राप्त कर धारकों

ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खूंटी पुलिस के प्रति आभार प्रकट किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को गुम-चोरी हुए मोबाइल फोन से संबंधित शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने से तथा सीआईआर पोर्टल का अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग करते हुए मोबाइल फोन की बरामदगी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई कि मोबाइल फोन गुम अथवा चोरी होने की स्थिति में तत्काल अपने नजदीकी थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए मोबाइल से संबंधित आवश्यक विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि एवं अन्य तकनीकी माध्यमों के जरिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त आमजनों के बीच सीआई पोर्टल के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु थाना स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार करने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

चीनी के बढ़ते दामों के बीच थोक गोदामों का निरीक्षण



मेदिनगर, पलामू/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। बढ़ते चीनी के दामों के बीच मंगलवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में कृषि बाजार प्रांण, बैरिया डालटनगंज स्थित चीनी के थोक व्यवसायियों के गोदामों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मेसर्स गौरव ट्रेडिंग, मेसर्स हार्दिक इंटरप्राइजेज, मेसर्स सुनील गोस्वामी, मेसर्स एस.बी. सेल एवं डालटनगंज ट्रेडर्स के गोदामों की जांच की गई। जांच के दौरान व्यवसायियों को प्रतिदिन चीनी की प्राप्ति एवं बिक्री का पंजी संधारित करने, एकरारनामा के अनुसार

चिन्हित गोदाम में ही चीनी का भंडारण करने तथा वर्तमान में चीनी की किल्लत को देखते हुए अधिक मूल्य पर बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्टॉक से संबंधित बोर्ड को प्रतिदिन अद्यतन रखने तथा किसी भी परिस्थिति में सात दिनों से अधिक अवधि का चीनी का भंडारण नहीं करने का निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि चीनी की उपलब्धता एवं कीमतों पर प्रशासन की लगातार नजर है। निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यवसायियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

10 हाथियों के झुंड ने रौंदी धान की फसल

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

रनिया। रनिया प्रखंड के ग्रामीण और जंगली इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक धमने का नाम नहीं ले रहा है। रात बोंगतेल गांव में करीब 10 हाथियों के झुंड ने खेतों में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने खेत में लगी धान की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। रात में हाथियों के गांव के आसपास पहुंचने से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है।

ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के कारण क्षेत्र में लगातार फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी गयी है। पीड़ित किसानों ने वन विभाग से क्षतिग्रस्त फसल का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने और फसल व जान-माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की है।

जेएसएलपीएस कार्यों में लापरवाही पर छह बीपीएम से स्पष्टीकरण

मेदिनीनगर, पलामू, नवबिहार टाइम्स संवाददाता। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (खछड) की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न आजीविका गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में कृषि, उद्यमिता विकास, फूली-झानो आशीर्वाद योजना, बैंक फ्लिकेज एवं स्वयं सहायता समूहों के सशक्तीकरण सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही सामाजिक विकास के कार्यों में तेजी लाने तथा लॉबित ग्रांट का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने फूली-झानो आशीर्वाद योजना का निर्धारित लक्ष्य अधीक्षक, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बीपीओ सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।



चैनपुर में दीदी कैफे खोलने की दिशा में कार्रवाई करने को कहा। समीक्षा के दौरान लो-कोष का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर छत्रपुर बीपीएम से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया गया। वहीं, आजीविका उपह रजिस्टर के कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उंटारी रोड, पाटन, हुसैनबाद, चैनपुर एवं मनातु के इष्ट से भी स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया। बैठक में पिछले माह के अनुपालन कार्यों की भी समीक्षा

की गई। कोयल अप्रैल पार्क में मैनाघर बढ़ाने के निर्देश के अनुपालन में अब 160 दीर्घियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।बैठक में जेएसएलपीएस की जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनीता सी. के.के.एड, जिला प्रबंधक अख्तर अंसारी, नवल किशोर, मिथलेश कुमार, विकास खलखो, प्रवीण सिंह समेत सभी प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

